

जल-जीवन-हरियाली के लिए पांच करोड़ से भी ज्यादा ने बनाई मानव शृंखला

महा अभियान ▶ बिहार में 18 हजार किलोमीटर लंबी कतार में खड़े होकर लोगों ने दिया संदेश-जल-हरियाली है, तभी जीवन और खुशहाली है

अरविंद शर्मा, पटना

बिहार में रविवार को पांच करोड़ 16 लाख से भी ज्यादा लोगों ने जल-जीवन-हरियाली एवं नशामुक्ति के पक्ष में और बाल विवाह एवं दहेज प्रथा के खिलाफ 18 हजार 34 किमी लंबी शृंखला बनाकर दुनिया को रास्ता दिखाया। इस महाभियान का साक्षी बना पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान, जहां बिहार के नक्सों से चारों दिशाओं में निकलकर मानव कतार पूरे प्रदेश में फैल गई। सीमावर्ती प्रदेशों उप्र, झारखंड और बंगाल के साथ-साथ पड़ोसी देश नेपाल को स्पर्श करते हुए पूरी दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि जल और हरियाली है, तभी जीवन है, खुशहाली है।

दूटें दो रिकॉर्ड : जल-जीवन-हरियाली के समर्थन में इस बार बनाई गई मानव शृंखला ने पिछले दो रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। 2017 और 2018 के रिकॉर्ड के मुकाबले जहां सर्वाधिक लोग इस बार शामिल हुए वहीं लंबाई के मामले में भी इसने विश्व कीतिमान बनाया। प्रदेश के मुख्यसचिव दीपक कुमार ने बताया कि जल-जीवन-हरियाली एवं नशा मुक्ति के पक्ष तथा दहेज प्रथा और बाल विवाह उन्मूलन के लिए बनाई गई शृंखला में 5,16,71,389 लोग शामिल हुए। इन लोगों ने एक दूसरे का हाथ थामकर कुल 18,034 किलोमीटर लंबी शृंखला का निर्माण किया। बिहारवासियों ने पहली बार 21 जनवरी,



गांधी मैदान में जल-जीवन-हरियाली अभियान के साथ-साथ नशामुक्ति, दहेज प्रथा एवं बाल-विवाह उन्मूलन के संदेश के साथ आयोजित मानव शृंखला का शुभारंभ करते बाएं से पांचवे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी एवं बिहार विधान सभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव यूनाइटेड नेशन प्रतिनिधि अतुल बग्राई, मुख्यमंत्री के दाएं जलपुरुष राजेन्द्र सिंह व अन्य ।

2017 को 11292 किमी की मानव शृंखला बनाई थी। जिसमें 3.5 करोड़ से अधिक लोगों ने हाथ से हाथ जोड़कर नशा मुक्ति के पक्ष में आवाज बुलंद की थी। इसके बाद 21 जनवरी, 2018 को बिहारवासियों ने बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन के लिए 14 हजार किमी की शृंखला बनाई। राज्य के महासचिव का दावा है कि बिहार ने ही मानव शृंखला का विश्व रिकॉर्ड कायम

किया है।
आपें घंटे के लिए थम गया वक्त : रविवार दोपहर घड़ी ने जैसे ही 11.30 बजाया, वैसे ही पांच करोड़ से ज्यादा हाथों ने एक दूसरे को आत्मीयता से थाम लिया। ऊंच-नीच, बड़ा-छोटा का भेद खत्म। मुलाजिमों और हाकिमों के बीच अद्भुत समन्वय था। सबके चेहरे पर चमक थी। प्रदेश की विभिन्न जेलों में कैदियों ने भी

शृंखला बनाई। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सुशील मोदी, जल पुरुष राजेन्द्र सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी इस आयोजन के गवाह बने। अगली पीढ़ी की हिफाजत की भावना और समर्पण की लंबी कतार में पूरा बिहार आधा घंटा खड़ा हुआ।

जो जहां था, वहीं खड़े होकर प्रकृति से प्यार का इजहार किया। पिछली दो मानव

एक नजर में	
मानव शृंखला की कुल लंबाई	18034 किमी
शामिल लोग	5,16,71,389
मॉनीटरिंग को हेलिकॉप्टर	7
प्रयोग में लाए गए ड्रोन	100

आकलन को आई दो संस्थाएं

बिहार में जल-जीवन-हरियाली के समर्थन में बने वाली मानव शृंखला के विश्व रिकॉर्ड आकलन के लिए दो संस्थाएं बिहार आईं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने बताया कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम के सदस्य पटना में थे जो यह आकलन कर रहे थे कि मानव शृंखला का विश्व रिकॉर्ड किस प्रकार से बना। संसाधनों की कमी का हवाला देकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम रिकॉर्ड के आकलन को इस आयोजन में शामिल नहीं हुई। उम्मीद है कि जल्द ही इसका सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा।

शृंखलाओं के कीर्तिमान के बाद प्रकृति के पक्ष में ऐसी एकजुटता और संकल्प शक्ति के प्रदर्शन से दूसरे प्रदेशों को भी प्रेरणा मिलेगी।

तो सियासत से कुछ यूं कमान थाम लेता है समाज

मनोज झा, पटना

रविवार की सर्द सुबह और छुट्टी का दिन, बादल और कोहरे के बीच दुबका सूरज, वातावरण में सिरसिरी-सी ठंड, लेकिन आम जनजीवन में एक अजीब-सी उमंग। पौ फटते ही पूरे बिहार में सियासत की अबूझ परछाइयों से दूर नागरिक समाज एक अलग उत्साह और जल्दी में नजर आ रहा था। किसी को कोई बुलावा या न्योता नहीं, कहीं कोई चोट या चुनाव भी नहीं, लेकिन जाने और जानने की जल्दी सभी को थी। एक ऐसे मिशन से जुड़ने के लिए, जिसका तुरंत कोई नतीजा भी नहीं आना है और इसका सुखद परिणाम शायद हमारी भावी पीढ़ी को भोगना है। बावजूद इसके, पांच करोड़ से ज्यादा लोग न सिर्फ स्वतः स्फूर्त घरो से बाहर निकले, बल्कि सड़क, मैदान, पानी और पहाड़ पर साथ आते गए, एक हाथ से दूसरे का हाथ जोड़ते रहे और 18 हजार किलोमीटर से ज्यादा लंबा एक कतार बना ली। दरअसल, यह बिहार की माटी से उठी एक समवेत पुकार है कि पानी और हरियाली ही एकमात्र रास्ता है, मानवता का मुक्तिपथ है। इन्हें बचना होगा, इन्हें सहेजना होगा, इन्हें संवारना ही होगा।

40 फीसद से ज्यादा आबादी जुड़ी : प्रदेश सरकार के जल-जीवन- हरियाली मिशन के इस पड़ाव की विहंगमता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश की 40 फीसद से ज्यादा आबादी इस अभूतपूर्व मानव शृंखला से जुड़ी। बूढ़े-बच्चे, नर-नारी, किसान-जवान, नेता-अभिनेता, शक्त-अशक्त, कामगार-बेरोजगार आखिर कौन था, जिसने हाथ से हाथ मिलाने में कोई गुरेज किया? छुट्टी के दिन आमतौर लोग थोड़े अलसाए और उनींद-से रहते हैं। लेकिन कल (19 जनवरी) का रविवार भी पर्यावरण के प्रति समाज की आश्चर्यजनक जागृति देखकर मानो गदगद हो गया। लोग पर्यावरण की चिंता में डूबकर घरों से खुद बाहर निकले। ऐसा भी नहीं कि सभी को कहीं एक स्थान पर किसी आयोजन में पहुंचना था या किसी को सुनना था। प्रदेश भर के तमाम जिलों में शहर, गांव, कस्बे, जहां जिसे सहूलियत थी, वहां पहुंचे और मानव शृंखला की एक-एक कड़ी बनते गए। मानव शृंखला के कीर्तिमान को देखकर तो एक बार के लिए ऐसा ही लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी शायद यह अंदाजा न हो कि पर्यावरण के प्रति उनकी चिंता में समाज

इस तरह दिल खोलकर साथ देगा। इससे यह भी साबित हुआ कि पर्यावरण के प्रति मुख्यमंत्री की चिंता कितनी वास्तविक और ठोस धरातल पर खड़ी है।

दिखे कई आश्चर्यजनक दृश्य: राजनीति में आज की गलाकाट प्रतिस्पर्धा के बीच पर्यावरण जैसे सरोकार को लेकर समाज का एकजुट हो जाना, उसका जाग जाना वाकई अभूतपूर्व है। पूरे प्रदेश में बनी मानव शृंखला के दौरान कई आश्चर्यजनक दृश्य देखने को मिले। मल्लाहों ने जमीन पाने का इंतजार नहीं किया और मानव शृंखला बनाने के लिए नदियों में ही अपनी नौकाओं को एक दूसरे से जोड़ लिया। कहीं अंत्येष्टि स्थल पर धकती चिता को छोड़ लोग हाथ से हाथ जोड़कर खड़े हो गए तो कहीं गृहणियां चौका-चूल्हा छोड़ सड़कों पर निकल आईं और एक से दूसरे का हाथ जोड़ लिया। अवकाश के बावजूद लाखों स्कूली बच्चे इस मानव शृंखला की कड़ियां बने, बुजुर्गों ने लाठी का सहारा लिया तो दिव्यांग व्हील चेयर पर आए। गवैयों ने गा-बजाकर जल का आचमन किया तो किन्नरों ने अपनी वेशभूषा में हरियाली का हार पहना। पूरे प्रदेश ने जल-जीवन-हरियाली मिशन को अब अपनी गोद में ले लिया है।

न्यूज गैलरी

वाट्सएप में आई तकनीकी बाधा, यूजर ने किया ट्रोल

नई दिल्ली : भारत समेत दुनिया के कई देशों में रविवार को वाट्सएप की सेवाएं बाधित रही। इससे नाराज यूजर ने टिवटर पर हैशटैग वाट्सएपडाउन को ट्रोल कर दिया। लोगों ने तरह-तरह के मीम और चुटकुले साझा करने शुरू कर दिए। शाम करीब चार बजे शुरू हुई यह परेशानी दो घंटे से भी ज्यादा समय तक बनी रही। दुनियाभर में वाट्सएप के लाखों यूजर वीडियो, फोटो, जीआइएफ, ऑडियो व स्टीकर साझा नहीं कर पा रहे थे। सोशल मीडिया की निगरानी करने वाली वेबसाइट डाउनडिटेक्टर के अनुसार, भारत, यूरोप, ब्राजील और दक्षिणपूर्व एशिया में यह परेशानी शाम करीब चार बजे शुरू हुई। नाराज वाट्सएप यूजर ने तकनीकी बाधा को टिवटर पर हैशटैग वाट्सएपडाउन के साथ ट्रोल कर दिया। (एएसिया)

पाकिस्तानी रेंजर्स ने गांवों को निशाना बना की गोलाबारी

हीरानगर : पाकिस्तानी रेंजर्स ने तीन दिन बाद फिर सीजफायर का उलंघन करते हुए हीरानगर सेक्टर के चक चंगा और छन्टांडा गांवों को निशाना बनाकर गोलाबारी की। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने भी गोलाबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। पाक रेंजर्स ने शनिवार देर रात पप्पू चक पोस्ट से गोलाबारी शुरू कर दी, जो रविवार सुबह साढ़े चार बजे तक जारी रही। इस दौरान पाक रेंजर्स ने गोलीबारी के साथ 81 व 51 एमएम के मोर्टार दागे, जो गांवों के बाहर खेतों में गिरे। (जास)

अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन दिलाने की मांग करेंगे

प्रथम पृष्ठ से आगे

भाजपा नेता का कहना है कि वह इस संबंध में मुख्यमंत्री से मिलकर उक्त जमीन अनुसूचित जातियों को ही दिलाने की मांग करेंगे, ताकि वे अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। अनुसूचित जाति के लोगों के अधिकारों का हनन हुआ है। इसलिए, जौहर ट्रस्ट के सभी सदस्यों पर एससी एसटी एक्ट में भी मुकदमा कराया जाए।

जमीन को सरकारी संपत्ति में दर्ज करने की होगी कार्यवाही : डीएम: जिलाधिकारी आनन्वेय कुमार सिंह का कहना है कि अभी उन्हें आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। आदेश मिलने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। जमीन को सरकारी संपत्ति में दर्ज करने के लिए प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी।

आर में मानव शृंखला में वृक्ष का दृश्य दर्शाती डॉ. नेमीवंद शार्षी विद्यालय की छात्राएं। जागरण

नीति आयोग के सदस्य बोले-कश्मीर में इंटरनेट पर गंदी फिल्में देखते हैं लोग

अहमदाबाद, प्रे्ट : नीति आयोग के सदस्य वीके सारस्वत की इस टिप्पणी पर विवाद खड़ा हो गया है कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद इंटरनेट पर पाबंदी से अर्थव्यवस्था पर कोई बड़ा असर नहीं पड़े, क्योंकि लोग वहां इंटरनेट पर गंदी फिल्में देखने के अलावा और कुछ नहीं करते। उनके इस बयान पर कश्मीर चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (केसीसीआइ) ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। चैंबर ने उन्हें पद से हटाए जाने की मांग की, जबकि माकपा के महासचिव सीताधाम येचुरी ने भी सारस्वत को निशाने पर लेते हुए कहा कि उन्हें संविधान पढ़ने की जरूरत है।

विवाद बढ़ने पर रविवार को सारस्वत ने सफाई दी कि उनके बयान को संदर्भ से हटकर पेश किया गया और वह कश्मीर के इंटरनेट के अधिकार के खिलाफ नहीं हैं। सारस्वत ने यह भी कहा कि अगर उनके गलत तरीके से पेश किए गए बयान से किसी की भावनाएं आहत हुईं हैं तो वह इसके लिए माफ़ी मांगते हैं। सारस्वत ने शनिवार को कहा था कि

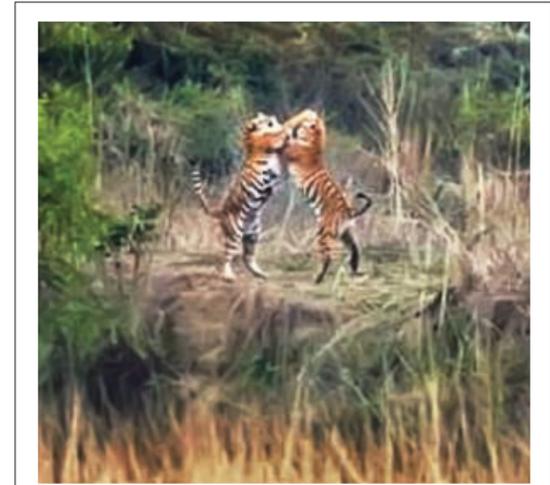
▶ कश्मीर चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री ने बयान की निंदा की

केसीसीआइ ने की निंदा

सारस्वत के बयान की केसीसीआइ (कश्मीर चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री) प्रेसीडेंट शेख आशिक ने निंदा करते हुए कहा कि जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति को यह शोभा नहीं देता कि वह कश्मीरी जनता की छवि खराब करने का काम करें। घाटी इंटरनेट शटडाउन के कारण पहले से बدهाल है, व्यापारिक नुकसान 18000 करोड़ रुपये हो चुका है। अगर सारस्वत सरीखे लोग जम्मू-कश्मीर के साथ कोई न्याय नहीं कर सकते तो उन्हें पद पर नहीं रहना चाहिए। गौरतलब है कि पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाए जाने के साथ ही इंटरनेट, लैंडलाइन और मोबाइल फोन की सेवाएं प्रतिबंधित कर दी गई थी। जम्मू में मोबाइल इंटरनेट को छोड़कर शेष सभी सेवाएं एक सप्ताह के भीतर ही शुरू कर दी गई थीं, जबकि कश्मीर में पोस्टपेड मोबाइल सेवा और अस्पताल जैसी जरूरी सेवाओं में इंटरनेट की बहाली चरणबद्ध तरीके से की गई। शनिवार को जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने घाटी में प्रीपेड मोबाइल सेवाओं की भी फिर से शुरुआत कर दी।

जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट पर पाबंदी इसलिए लगाई गई ताकि कुछ लोग सूचना का दुरुपयोग करके कानून एवं व्यवस्था के समक्ष संकट खड़ा करने का काम न कर सकें। धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट आफ इन्फार्मेशन एंड टेक्नालाजी के दीक्षा समारोह

में भाग लेने के बाद पत्रकारों से सारस्वत ने कहा, अगर कश्मीर में इंटरनेट नहीं है तो इससे क्या फर्क पड़ता है। आप वहां इंटरनेट पर क्या देखते हैं? वहां इससे कौन सा बिजनेस चल रहा है। गंदी फिल्में देखने के अलावा लोग और क्या करते हैं?



कार्बेट में वर्चस्व की जंग

कार्बेट पार्क में बाघों की संख्या बेशक बढ़ रही है, लेकिन आपसी जंग में वह अपनी जान भी गवां रहे हैं। कार्बेट के डिकाला क्षेत्र में वर्चस्व के लिए दो बाघ आपस में भिड़ गए। ऐसा नजारा बहुत कम देखने को मिलता है। जब दो बाघों की लड़ाई को कैमरे में कैद किया जा सके। शुक्रवार को रेरट हाऊस के सामने बाघों का संघर्ष काफी देर तक चला। सीटीआर के निदेशक राहुल ने बताया कि यह फोटो उन्हें एक पर्यटक ने अपलब्ध कराई है। संघर्ष में एक बाघ के घायल होने की सूचना है।

आउटरीच कार्यक्रम

कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों तक पहुंचे आठ मंत्री, पांच जिलों के दस ब्लॉकों में केंद्रीय योजनाओं की दी गई जानकारी

केंद्रीय मंत्रियों ने जम्मू-कश्मीर में वादे के साथ विकास की जगाई आस

राज्य ब्यूरो, जम्मू

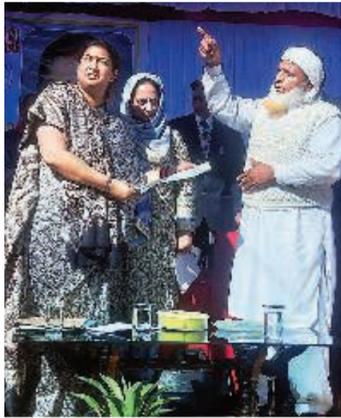
मोदी सरकार के मंत्रियों के कार्यक्रमों में पंचायत प्रतिनिधि ही नहीं, ग्रामीण भी अपनी समस्याओं को बताने के लिए बेहचक पहुंच रहे हैं। वह बेबाक अपनी बात रख रहे हैं। रविवार को जम्मू संभाग के विभिन्न जिलों में गए केंद्रीय मंत्रियों ने ग्रामीणों में विकास के नई आस जगाई है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अब जम्मू कश्मीर में विकास के रास्ते की रुकावट अनुच्छेद 370 हट चुका है। अब तेज विकास का वादा पूरा होगा। मोदी सरकार के आउटरीच कार्यक्रम के दूसरे दिन रविवार को आठ केंद्रीय मंत्रियों ने जम्मू संभाग के पांच जिलों के दस ब्लॉकों में लोगों के बीच जाकर उन्हें 370 हटने के बाद विकास के क्षेत्र की उपलब्धियां बताईं। उन्होंने लोगों से जमीनी स्तर पर फीडबैक भी लिया। मंत्रियों में स्मृति ईरानी, महेंद्रनाथ पांडे, अर्जुन राम मेघवाल, वी मुरलीधरन, अनुराग ठाकुर, डॉ. जितेंद्र

अनुराग ठाकुर ने तेज विकास के वादे को दोहराया

अनुराग ठाकुर ने नगरों में मोदी सरकार के तेज विकास के वादे को दोहराया। मनरेगा, जन धन जैसी योजना का उदाहरण दिया। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हो गए व विकास को भी बढ़ावा मिला है। केंद्रीय योजनाओं में उन्होंने पंचों, सरपंचों का सहयोग भी मांगा। राज्यसभा के सांसद शमशेर सिंह मन्हास के साथ नगरों में कार्यक्रम में हिस्सा लेने से पहले केंद्रीय मंत्री ने नगरों से कड़ूल-बटाल सड़क का भी उद्घाटन किया।

सिंह, पीयूष गोयल, अश्विनी चौबे व आरके सिंह शामिल थे। मंत्रियों ने जम्मू जिले के अखनूर, डंसाल, नगरों, रियासी जिले के कटड़ा, पैथल, कटुआ जिले के बसोहली, बिलावर, ऊधमपुर जिले के उधमपुर, की खिलेनी व सांबा जिले के घगवाल ब्लॉकों में कार्यक्रम किए। जम्मू जिले में रेलवे मंत्री पीयूष गोयल, कौशल विकास मंत्री महेंद्रनाथ पांडे व वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने रविवार दोपहर को अखनूर, नगरों, डंसाल जिले के सांघ, सरपंचों के साथ बैठकी। लोगों को उन्होंने विश्वास दिलाया कि अब ग्रामीण

विकास की राह में फंड की कमी नहीं होगी। उन्होंने पंचों, सरपंचों, ब्लॉक डेवलपमेंट कार्डसिल के अध्यक्षों के मसंलों को जाना कि राज्य में विकास व केंद्र प्रायोजित योजनाओं से लोगों की तकदीर बदलने की खिलेनी व सांबा जिले के घगवाल ब्लॉकों में कार्यक्रम किए। जम्मू जिले में रेलवे मंत्री पीयूष गोयल, कौशल विकास मंत्री महेंद्रनाथ पांडे व वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने रविवार दोपहर को अखनूर, नगरों, डंसाल जिले के सांघ, सरपंचों के साथ बैठकी। लोगों को उन्होंने विश्वास दिलाया कि अब ग्रामीण



केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जम्मू-कश्मीर में माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटड़ा के मुरी गांव का दौरा किया। ग्रामीणों ने ईरानी को समस्याओं से अवगत कराया। जागरण

जम्मू-कश्मीर को जल्द मिलेगा बड़ा औद्योगिक पैकेज : गोयल

राज्य ब्यूरो, जम्मू

केंद्रीय वाणिज्य एवं रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर देश का हीरा है। इस प्रदेश के लिए जल्द बड़ा औद्योगिक पैकेज दिया जाएगा। कश्मीर हमेशा धरती का स्वर्ग रहेगा। घाटी के सुरक्षित माहौल में पर्यटकों का आना शुरू हो गया है। पूरी उम्मीद है कि कश्मीर में बड़े पैमाने पर निवेश होगा। जम्मू जिले के अखनूर में कटड़ा-बनहाल रेल लिंक बन जाने से विकास को तेजी मिलेगी। जम्मू-कश्मीर में सात महीनों में विकास के क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। यह मुहिम जून 2018 को राज्यपाल शासन लागू होने के बाद शुरू हुई थी। सात दशकों से नजरअंदाज

▶ केंद्रीय वाणिज्य मंत्री बोले- कश्मीर में बड़े पैमाने पर निवेश की उम्मीद

जम्मू-कश्मीर के लोग अब तेज विकास की इस मुहिम की निगरानी कर रहे हैं। गोयल ने कहा कि पहले रियासी में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का काम धीमी गति से चल रहा था। अब इसे तेजी दी गई है। फंड खत्म हो जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक निवेश होगा। जम्मू जिले के अखनूर में कटड़ा-बनहाल रेल लिंक बन जाने से विकास को तेजी मिलेगी। जम्मू-कश्मीर में सात महीनों में विकास के क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। यह मुहिम जून 2018 को राज्यपाल शासन लागू होने के बाद शुरू हुई थी। सात दशकों से नजरअंदाज